

credited, and thereafter to take action. Now, as the hon. Member said, the previous Finance Minister had given an assurance of strong action. Well, that strong action is being taken, namely, criminal prosecutions have been launched against the defaulting employers.

**SHRI KALYAN ROY :** What are the names ? I asked for the names.

**SHRI H. M. PATEL :** If you want names, you should have given me notice.

**SHRI KALYAN ROY :** On a point of order, Sir. Why should I give notice ? He himself admits that quite a few employers have failed to pay the deposit within the specified time. I want to know how many of them belong to the big business houses and what specific action has been taken against them. Why should I give notice ? The question is clear, precise and properly framed.

**SHRI H. M. PATEL :** I cannot bring all the material. I will certainly give whatever information he wants. But naturally I must be told what details he wants.

**SHRI KALYAN ROY :** Will he lay it on the Table of the House ?

**SHRI H. M. PATEL :** I may say that the question did not say that the names of these defaulting employers should be laid.

**SHRI KALYAN ROY :** Please, Sir, it is a question of procedure. Generally questions are given in the form of (a), (b) and (c). The names should be ready with the Minister. We cannot give a 10 page question. I asked a specific question. How many of them belong to the big business houses ? I mentioned categorical names—Singhanias, Birlas, Bird and Company, Goenkas and Jains.

**SHRI H. M. PATEL :** Mr. Deputy Chairman, I have just received information that the names of all the defaulting employers were laid on the Table of the House on the last occasion.

**SHRI KALYAN ROY :** That is incomplete.

**SHRI S. W. DHABE :** Sir, this scheme has caused great resentment

among the working class for a number of reasons. One of them is that the accounts are not given and defaults are made by the employers. There is a universal demand for scrapping this scheme. The Act is coming to an end in the month of June or so. Will the Minister say whether the scheme will be scrapped so that this problem is solved once and for all and the entire amount impounded is refunded back to the workers within two months ?

**SHRI H. M. PATEL :** Mr. Deputy Chairman, Sir, on this question, I have already said that this matter is a policy matter which is under consideration and it will be dealt with at the time of the Budget.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN :** Next question.

### दिल्ली गोरखपुर विमान सेवा

\* 8. श्री नागेश्वर प्रसाद शाही :†  
श्री नत्थी सिंह :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स दिल्ली तथा गोरखपुर के मध्य दैनिक विमान सेवा शुरू करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक शुरू की जाने वाली है ?

### †Delhi-Gorakhpur air service

8. SHRI NAGESHWAR PRASAD  
SHAHI : †  
SHRI NATHI SINGH :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the Indian Airlines proposes to introduce daily air service between Delhi and Gorakhpur ; and

(b) if so, by when the service is likely to be introduced ?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Nageshwar Prasad Shahi.

†English translation.

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक):** (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स इस समय दिल्ली-कानपुर-गोरखपुर-कलकत्ता सेक्टर पर गोरखपुर के लिए सप्ताह में तीन बार की विमान सेवा परिचालित कर रही है। गोरखपुर से को आने जाने वाले यातायात को दृष्टि में रखते हुए सेवा की आवृत्ति में फिलहाल कोई वृद्धि करना उचित प्रतीत नहीं होता।

[THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) and (b) Indian Airlines are presently operating thrice weekly air service to Gorakhpur on the Delhi-Kanpur-Gorakhpur-Calcutta Sector. The traffic to and from Gorakhpur does not justify any further increase at present in the frequency of the service to Gorakhpur.]

**श्री नागे.वर प्रसाद शाही :** श्रीमन्, जैसा कि मैं पहले चार पांच साल से कहता चला आ रहा हूँ कि स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान की गई थी और हर वर्ष लाखों की संख्या में बर्मा चाइना और दक्षिण पूर्वी-एशिया के देशों से कई यात्री कुशीनगर, लुम्बनी के लिये आते हैं। यह दोनों स्थान जो कि बुद्ध भगवान के जन्म स्थान हैं दोनों गोरखपुर के पास ही पड़ते हैं। यहां जाने वाले व्यक्तियों को बहुत परेशानी होती है। इन यात्रियों को या तो बनारस में लैंड करना पड़ता है, या लखनऊ में लैंड करना पड़ता है वहां लगभग से 200 रुपए खर्च करके कशी-नगर या लुम्बनी जाना पड़ता है। गोरखपुर यहां से नजदीक है और इसी ख्याल से पंडित नेहरू ने यहां विशेष व्यवस्था की थी। सरकार ने वहां के लिये यदि किसी प्रकार से ध्यान भी दिया तो केवल सप्ताह में तीन दिन ही हवाई जहाज भेजने की व्यवस्था है और मंत्री महोदय

कह रहे हैं कि उस सेवा को बढ़ाने की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि जिस रूप से यह सेवा चलाई जाती है और विशेष तौर से फारेन एक्सचेंज के आनिंग के ख्याल से और विदेशी लोगों को सुविधा देने के ख्याल से—जो लोग अमरीका से आते हैं या यूरोप से आते हैं, बीचेज में जाना चाहते हैं और वहां समुद्र में नंगा स्नान करना चाहते हैं उनके लिये तो विशेष सुविधा की व्यवस्था की गई है और जो बौद्ध यात्री आते हैं उनके लिये मंत्री महोदय का विभाग जो है वह सोचना भी नहीं चाहता है। क्या मंत्री महोदय इस संबंध में कोई तरीका सुझायेंगे ताकि इन तीर्थ यात्रियों की सुविधा की व्यवस्था हो सके और वहां के लिये दैनिक विमान सेवा चालू की जा सके?

**श्री पुरुषोत्तम कौशिक :** उपसभापति महोदय, सरकार को दैनिक विमान सेवा चालू करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि वहां यात्रियों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण हमें सप्ताह में तीन दिन करना पड़ा। मैं सदन की जानकारी के लिये और माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कह देना चाहता हूँ कि जो हमने तीन दिन सेवा उपलब्ध कराई है उसमें भी 2 लाख 90 हजार प्रति माह का नुकसान हो रहा है और ऐसी स्थिति में यदि हम दैनिक सेवा चालू करेंगे तो इस नुकसान की संख्या और बढ़ जायेगी। इसलिए इस आधार पर मैं यह निवेदन करना म्चाहता हूँ कि सरकार के लिये यह संभव नहीं है कि दैनिक सेवा उपलब्ध कराई जाय।

**श्री नागे.वर प्रसाद शाही :** अभी सेवा शुरू हुए मुश्किल से एक दो महीने हुए और आपने नुकसान जोड़ दिया, बाद की संभावनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया।

**श्री नत्थो सिंह :** मंत्री जी के पास पर्यटन विभाग भी है। मेरा निवेदन है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वह एक पर्यटन केन्द्र बने और ज्यादा से ज्यादा यात्री वहाँ जायें और यह विमान सेवा उन को लाभदायक हो तथा वह प्रतिदिन चले, इस के लिये मंत्री महोदय का विभाग क्या कदम उठा रहा है ?

**श्री पुरुषोत्तम कौशिक :** इस के लिये हम पूरी सुविधा देने की कोशिश करेंगे कि जो टूरिस्ट है वे अधिक से अधिक इधर आकर्षित हो। इस बात का पूरा प्रयास किया जायेगा और इसी आधार पर निश्चित रूप से दैनिक सेवा चालू करने पर विचार किया जायेगा।

**श्री श्यामलाल यादव :** उपभाषित महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पहले यह सर्विस बराबर प्रति दिन दिल्ली से वाराणसी तक जाती थी। उस सर्विस को तीन दिन करके गोरखपुर कर दिया गया है और इन तीन दिनों में यह हवाई जहाज वाराणसी नहीं जाता। वाराणसी एक बड़ा टूरिस्ट केन्द्र है। वहाँ पर बोईंग सर्विस चलती है खजूर हो आगरा होते हुए कांठामंडू सर्विस चलती है। यह पूरी की पूरी सेवा वर्ष के अधिकांश महीनों विदेशी यात्रियों से भरी रहती है। दूसरी सर्विस जो थी वह प्रति दिन वाराणसी से कानपुर थी जो कि लखनऊ होकर जाया करती थी। उस में लोकल पैसेजर जो होते थे वह जाया करते थे अब जो यह सेवा सरकार ने शुरू की है यह वाराणसी को टच नहीं करती जिससे वाराणसी जाने वाले दूसरे यात्रियों को बहुत अधिक असुविधा होती है। कई बार हम लोगों को भी असुविधा होती है। इसलिये इस और मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए

अनुरोध करूंगा कि थोड़ी छोटी सेवा तो वाराणसी के लिये प्रति दिन रहनी चाहिये। हफ्ते में सातों दिन रहनी चाहिये जिससे कि वह यात्रियों का जो रश रहता है उस को संभाल सके। वहाँ 3 दिन में एक सर्विस होने से बहुत अधिक कठिनाई होती है, विदेशी यात्रियों को असुविधा होती है और लोकल यात्रियों को भी।

**श्री नागेश्वर प्रसाद शाही :** यह तो सुझाव है, सवाल नहीं है।

**श्री श्यामलाल यादव :** आप ही क्यों मंत्री का स्थान ले ले। मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिय।

**श्री पुरुषोत्तम कौशिक :** इस सुझाव का लाभ उठाने की दृष्टि से हम विचार करेंगे।

**डा० रामकृपाल सिंह :** मैं उपभाषित महोदय, आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विमानन और पर्यटन मंत्री होने के नाते उन के ध्यान में यह होगा कि वैशाली प्राचीन लिच्छिवियों का बहुत ही प्रजातंत्र का केन्द्र था। उस का विकास करने के हेतु मुजफ्फरपुर दिल्ली के लिये वाराणसी होते हुए हफ्ते में दो दिन प्लेन सर्विस थी पहले। तो किस आधार पर उस सर्विस को बन्द किया गया ? क्या सरकार वैशाली के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए और चूंकि गंगा उत्तर पूर्वी बिहार तक कहीं भी यातायात उड्डयन विभाग दिल्ली से उस को जोड़ता नहीं इसलिये इस बारे में सरकार ने क्या योजना बनाई है कि मुजफ्फरपुर को जो पहले एयर लिंक था दिल्ली से, और वैशाली के महत्व को देखते हुए, फिर से उस को एयर लिंक किया जाय ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मूल प्रश्न से यह प्रश्न जुड़ा हुआ नहीं है। सवाल उस से उठता नहीं इसलिये नोटिस चाहिये।

\*9. [ *The questioner (Shri Khurshed Alam Khan) was absent. For answer, vide col. 39-40 infra* ]

#### Closed textile mills

\*10. SHRI S.W. DHABE : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the number of closed textile mills in the country and the reasons for their closure ; and

(b) whether any closed textile mills were taken over by Government during the year 1976 and if so, what is their number ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) :

(a) Out of 702 cotton textile mills, 32 mills are closed. In most cases, closure has been mainly due to financial losses resulting from various factors such as uneconomic size, obsolescence of machinery, mis-management and rise in raw material prices. In two cases, there has also been labour trouble.

(b) During the calendar year 1976, the management of 4 mills was taken over, 2 for management by Central Government and 2 for management by the State Governments concerned.

SHRI S. W. DHABE : Sir, the honourable Minister is aware of the importance of the textile industry in the country. I would like to know from him whether he is also aware of the fact that the closure of these mills has affected production materially in the country and also the employment of the workers working therein. Have any steps been taken under the Industries (Development and Regulation) Act to appoint an inquiry committee to go into these things and what steps have been taken to take over these mills so that they can start working immediately ?

SHRI MOHAN DHARIA : Sir, this House may be aware that the Central Government along with the State Govern-

ments has taken over 105 sick mills and has opened them and I fully share the view of the honourable Member that these mills, when they are closed down, affect our production and also there is the problem of retrenchment causing distress to thousands of families. 24,832 employees are out of job for the time being and more than 5,500 looms and 6,28,168 spindles are out of order. So, under these circumstances, we are very much concerned about it. But, Sir, before we finance, it is very much necessary that these units should be viable and it is in this context that all possible efforts are being made in consultation with the State Governments and the financing institutions so that we can see that they resume their work as early as possible.

SHRI S.W. DHABE : Sir, Will the honourable Minister consider the long-standing suggestion of the trade unions like the INTUC and others that preventive steps should be taken before the closure of the mills by instituting proper inquiries and by having standing vigilance committees so that the Government is aware now and then as to which are the mills which are likely to close down and which are the mills which are going to get into trouble? Will the Government consider the suggestion of having standing vigilance committees so that such closures can be prevented and anticipatory action can be taken in order to see that the workers and the country do not suffer at all ?

SHRI MOHAN DHARIA : Sir, it is a very good suggestion. I can assure the honourable Member and the House that it shall be the endeavour of the Central Government to take not only the management but also the various trade unions, into confidence and I would very much like to accept this suggestion of the honourable Member and get it examined. At the same time, Sir, I would like to tell the honourable Member that as a matter of right, he, being a trade union leader, and others can immediately convey to the Government any information which they may have if there is any apprehension regarding the closure of the mills and appropriate action will certainly be taken.